बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग
।। संकल्प ।।

विषयः– केन्द्र प्रायोजित Smart City Mission योजना के अन्तर्गत पटना शहर को Smart City के रूप में विकसित करने हेतु एक SPV कम्पनी "पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड कम्पनी" के MoA एवं AoA सहित गठन के प्रस्ताव पर स्वीकृति एवं योजना पर अनुमानित व्यय 2776.16 करोड़ (दो हजार सात सौ छिहत्तर करोड़ सोलह लाख) रूपये की प्रशासनिक स्वीकृति तथा इसमें योजना के लिए 465.00 करोड़ (चार सौ पैंसठ करोड़) रूपये एवं कंपनी के निबंधन के लिए 2.50 करोड़ (दो करोड़ पचास लाख) रूपये राज्यांश के रूप में व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं०–K-15016/157/2015-SC-I दिनांक–28/06/2017 द्वारा Smart City योजना के अन्तर्गत पटना शहर का चयन किया गया है। इसका उद्देश्य पटना शहर का आर्थिक विकास करना और बेहतर स्थानीय क्षेत्र विकास और प्रौद्योगिकी का उपयोग करके विशेष तौर से प्रौद्योगिकी जो स्मार्ट परिणामों का मांग प्रशस्त करती है, से पटना शहर के लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। क्षेत्र–आधारित विकास (Area Based Development) एवं पूर्ण शहर आधारित विकास (Pan City Development) की योजनायें ली जायेगी। स्मार्ट समाधानों के प्रयोग से शहरी अवस्थापना और सेवाएँ बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी, की जानकारी और आंकड़ो का उपयोग कर सकेंगे। इससे यहाँ के नागरिकों का चहुँमुखी विकास, जीवन की गुणवत्ता सुधार, रोजगार के अवसर और सभी के लिए विशेष तौर से गरीबों और वंचितों की आय में वृद्धि हो सकेगा, जिससे पटना शहर के समावेशी विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। उक्त कार्यों को सम्पादित करने हेतु एक SPV कम्पनी "पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड कम्पनी" का गठन किया जाना प्रस्तावित है। यह SPV कम्पनी एक्ट 2013 के तहत पंजीकृत होगी तथा इसका निबंधित कार्यालय पटना शहर में अवस्थित होगा। कम्पनी का उद्देश्य पटना शहर को 2021 तक स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने हेतु कार्य योजना तैयार कराना, मूल्यांकन, स्वीकृति राशि की विमुक्ति, प्रबंधन, संधारण, अनुश्रवण तथा अन्य सभी आवश्यक कार्यों को सम्पादित किया जाना है।

2. योजना के लिये आवश्यक निधि के स्त्रोत फंडिग पैटर्नः–

पटना स्मार्ट सिटी योजना की अनुमानित लागत राशि 2776.16 करोड़ (दो हजार सात सौ छिहत्तर करोड़ सोलह लाख) रूपये हैं, जिसमें भारत सरकार एवं राज्य सरकार की हिस्सेदारी 930.00 करोड़ (नौ सौ तीस करोड़) रूपये में 50:50 के अनुपात में होगा। राज्य सरकार को अपनी हिस्सेदारी की राशि 465.00 करोड़ (चार सौ पैंसठ करोड़) रूपये की अतिरिक्त SPV के पंजीकरण हेतु 2.50 करोड़ (दो करोड़ पचास लाख) रूपये का व्यय भार वहन करना होगा। Convergence of ongoing Govt. of India schemes and Govt. of Bihar Schemes and ULB own sources से अनुमानित 982.31 करोड़ (नौ सौ बेरासी करोड़ एकतीस लाख) रूपये तथा जन निजी भागीदारी (PPP) से अनुमानित 800.37 करोड़ (आठ सौ करोड़ सैंतिस लाख) रूपये की धनराशि प्राप्त होंगे। स्मार्ट सिटी मिशन को एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) के रूप में चलाया जायेगा और केन्द्र सरकार द्वारा आगामी 5 वर्षों में प्रति वर्ष 100 करोड़ रूपये की राशि दी जायगी। इतनी ही राशि का योगदान, समान आधार पर, राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा। इस प्रकार, स्मार्ट सिटी विकास के लिए लगभग 1000 करोड़ (एक हजार करोड़) रूपये की धनराशि सरकार/यूएलबी को उपलब्ध होगी। भारत सरकार की निधियां और राज्य सरकार द्वारा समान योगदान परियोजना लागत के एक भाग को पूरी कर पायेंगे। शेष निधियां निम्नलिखित से जुटाने की प्रत्याशा है :–

i. राज्यों/यूएलबी को अपने स्वयं के स्त्रोतो से जैसे प्रयोक्ता शुल्क का संग्रहण, लाभार्थी प्रभार और प्रभाव शुल्क, भूमि के मुद्रीकरण, उधार और ऋण आदि।

ii. चौदहवें वित्त आयोग (एफएफसी) की सिफारिशों की स्वीकृति के कारण हस्तांतरित अतिरिक्त संसाधन।

iii. नवीकृत वित्तपोषण तंत्र जैसे यूएलबी की क्रेडिट रेटिंग के साथ नगरवालिका बांड, सामूहिक वित्त तंत्र, कर सवंर्धित वित्तपोषण (टीआईएफ)।

iv. केन्द्र सरकार की अन्य स्कीमें जैसे स्वच्छ भारत मिशन, अमृत, राष्ट्रीय विरासत शहर विकास और संवर्धन योजना (हृदय)।

v. वित्तीय संस्थानों से द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहित धरेलु और बाह्य दोनों स्त्रोतो से लीवरेज उधार बढ़ाकर।

vi. राज्य/संघ शासित प्रदेश राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना निधि (एनआईआईएफ), जिसकी घोषणा वित्त मंत्री द्वारा 2015 के अपने बजट भाषण में की गई है और जिसके इसी वर्ष गठन की संभावना है, से भी सहायता ले सकते हैं।

vii. पीपीपी के माध्यम से निजी क्षेत्र।

3. पटना स्मार्ट सिटी योजना के अधीन मदवार व्यय निम्न प्रकार होंगे :–

पटना स्मार्ट सिटी योजना की अनुमानित लागत व्यय 2776.16 करोड़ (दो हजार सात सौ छिहत्तर करोड़ सोलह लाख) रूपये हैं, जिसमें क्षेत्रीय आधारित विकास (Area based development) के व्यय हेतु 2542.54 करोड़ (दो हजार पांच सौ बियालिस करोड़ चौवन लाख़) रुपये जबकि पैन सिटी (Pan City Development) के विकास हेतु 233.62 करोड़ (दो सौ तैंतीस करोड़ बासठ लाख) रुपये कर्णांकित किया गया है :–

AREA BASED DEVELOPMENT (ABD) & Operation Smpoorna Nagar Vikas: PAN City Projects:-

	Project	Estimated Cost Capex/ Opex (In Crores)
A.	AREA BASED DEVELOPMENT (ABD)	
A.A	Operation Aadharbhoot: Core & Resilient Infra	135.79
A.A.1	Potable Water Supply	32.95
A.A.2	Smart Solution for Water Supply	10.44
A.A.3	Recycled Water Supply	34.00
A.A.4	Sewerage Network in ABD Area	51.90
A.A.5	Sanitation: Public Toilets (with bio-digesters)	2.00
A.A.6	e-Toilets	4.50
A.B	Operation Visanukulan: Decongestion	617.00
A.B.1	Redevelopment of Railway Station Area	433.00
A.B.2	Bankipur BSRTC TTMC	175.00
A.B.3	Intermediate Public Transport (IPT) Stands	9.00
A.C	Gaatisheel Patna: Seamless Mobility	342.45